Manufacture of tractors in the Public sector

1012. SHRI GEORGE FERNANDES:
SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA:
SHRI SITARAM KESRI:
SHRI SHRI CHAND GOYAL:
SHRI HARDAYAL DEVGUN:
SHRI S.M. BANERJEE:
SHRI R.K. SINHA:
SHRI K.P. SINGH DEO:
SHRI RAM AVTAR SHARMA:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any blue-print has been worked out for the manufacture of tractors in the public sector?

(b) how many applications for licence to manufacture tractors are pending from the private sector;

(c) whether Government would consider given priority to the production of tractors in the country; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F.A. AHMED): (a) Government have under consideration a proposal to set up a unit in the Public Sector for the manufacture of tractors. A final decision is yet to be taken.

(b) After delicensing of the tractor industry, 10 proposal have been received for the establishment of new undertaking for the manufacture of tractors with foreign collaboration.

One of these peoposals has been approved in principle. The firm concerned has recently submitted the final foreign collaboration agreement, the revised phased manufacturing programme and the application for the import of capital goods, which are under examinition. Two other firms in whose case payment of either lump-sum or recurring royalty to the proposed foreign collaborators was not involved, were asked to submit their application for the import of capital goods and revised phased manufacturing programme for Government's consideration. One of them has submitted the draft collaboration agreement. They have been asked to submit the application for the import of capital goods and revised phased manufacturing programme immediately. The other firm has failed to submit this information and accordingly their case has been treated as closed. One of the applicants has been asked to get the tractor, proposed to be taken up for manufacture, tested at the Tractor Testing Station, Budni before a final view is taken on their proposal. Two other applicants have been asked to submit the detailed schemes together with a letter from their collaborators expressing willingness to extend collaboration. These applications will be considered further after these details are received. Two schemes were sketchy and the parties have been asked to submit details. The remaining two schemes are under examination.

(c) The Agricultural tractor industry is included in the list of key industries and the industry is already being given priority in the matter of foreign exchange allocation for the import of capital goods and components.

(d) Does not arise.

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स

1014. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1970-71 के बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास काम की कमी की समस्या पैदा हो जायेगी और इसकी स्थापित क्षमता में से 50 प्रतिशत क्षमता बेकार पड़ी रहेगी ; और

(ख) क्या उपरोक्त कम्पनी में क्षमता अप्रयुक्त रहने का मुख्य कारण यह है कि चौथी योजना में बिजली पैदा करने में

बिजली की भारी मशीनों का कम प्रयोग किया जाना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० तथा हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि० भोपाल पर आगामी कुछ वर्षों में निर्माण का भार स्वाभाविक रूप से चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में विद्युत विकास के अन्तिम रूप से निश्चित किये जाने वाले कार्यक्रम पर निर्भर करेगा, क्योंकि ये उपक्रम मुख्य रूप से विद्युत उत्पन्न करने के भारी वैद्युत उपकरण बनाने के लिए स्थापित किये गये हैं। इस अवधि में जिस सीमा तक इन संयंत्रों में जितनी निर्माण क्षमता उत्पन्न की जायेगी उस सीमा तक विद्युत विकास कार्यक्रम लागू न हो सकने पर निर्माण क्षमता फालतू हो जायेगी। इस सम्बन्ध में स्थिति तब तक स्पष्ट नहीं हो सकेगी जब तक कि विद्युत विकास के लिए चौथी योजना अन्तिम रूप से निश्चित कर ली जाती। इन उपक्रमों में उत्पादन में यथासम्भव विविधता लाने के प्रयास किये जा रहे हैं जिससे भारी वैद्युत संयंत्रों की निर्माण क्षमता का यथासम्भव अधिकाधिक उपयोग किया जा सके।

सैन्ट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट

1015. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्ट्रल मैकेनिकल इन्जीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित तथा परीक्षित "ट्रैक्टर" कृषि प्रयोजनों हेतु लाभदायक सिद्ध हुए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनके निर्माण के लिए बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त संस्था द्वारा आविष्कृत कीटनाशी "स्प्रे" मशीनों के निर्माण के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सैंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक 20 अश्वशक्ति वाले कृषि ट्रैक्टर का विकास किया है। इसके दस आद्यरूपों के निर्माण में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है। उसने इस आद्यरूपों का ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र बुदनी, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, भारतीय टेक्नालाजी संस्था, खड़गपुर तथा कुछ चुने हुए कृषकों द्वारा परीक्षण किये जाने के प्रबन्ध कर लिए हैं। इन परीक्षणों के परिणाम उपलब्ध हो जाने के पश्चात् भारतीय परिस्थितियों में इस ट्रैक्टर की उपयोगिता का पता लग सकेगा।

(ख) माइनिंग ऐण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर ने इस ट्रैक्टर को बनाने का प्रस्ताव रखा है। उसने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० से मिलकर राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और इस संबंध में सिफारिश करने के लिए कहा है कि क्या सैंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया ट्रैक्टर या जीटर 2011 ट्रैक्टर चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की रिपोर्ट अप्रैल, 1969 के अंत तक मिल जाने की आशा है।

(ग) सैंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इस्टीट्यूट के अनुसार उनके द्वारा विकसित प्रथम कीटाणुनाशक स्प्रेयर का 1967 के प्रारम्भ से काफी परीक्षण किया जा चुका है। इसके निर्माण के लिए अभी तक किसी प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।